Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

शहरी व ग्रामीण जनसंख्या में आश्रित व कार्यशील जनसंख्या की स्थिति का आकलन

Dr. Padma Tripathi*

Associate Professor, Economics, K.K.P.G. College, Etawah

सारांश – *शहरी व ग्रामीण जनसंख्या में औसत आश्रित तथा कार्यशील जनसंख्या में तालिका नम्बर-अ-(i) में शहरी जनसंख्या में यह प्रकट होता है कि अजीतमल में कुल 20 परिवारों की 92 जनसंख्या में 28 लोग आश्रित हैं तथा 64 लोग किसी न किसी व्यवसाय में कार्यरत हैं। इस प्रकार लगभग 30.43 प्रतिशत लोग आश्रित तथा लगभग 69.56 प्रतिशत लोग कार्यशील हैं।*

बाबरपुर में कुल 20 परिवारों की 100 जनसंख्या में 36 लोग आश्रित तथा 64 लोग कार्यशील हैं जो क्रमशः 36 प्रतिशत तथा 64 प्रतिशत हैं।

अटसू में 20 परिवारों में औसत 102 जनसंख्या में 40.20 प्रतिशत आश्रित तथा 59.80 प्रतिशत कार्यशील हैं।

अनन्तराम में 20 परिवारों की 109 जनसंख्या में 46 लोग आश्रित तथा 63 लोग कार्यशील हैं जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 42.20 प्रतिशत तथा 57.80 प्रतिशत है।

सभी शहरी क्षेत्रों में औसतन 37.75 लोग आश्रित तथा 63 लोग कार्यशील हैं। आश्रित तथा कार्यशील लोगों के इस अनुपात से यह प्रतीत हो रहा है कि शहरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

तालिका नम्बर-अ-(ii) ग्रामीण जनसंख्या में औसत आश्रित तथा कार्यशील जनसंख्या का अवलोकन करने से यह प्रकट हुआ कि सांफर गांव में कुल 103 जनसंख्या में 29 लोग औसतन आश्रित तथा 74 लोग औसतन कार्यशील हैं जो कुल जनसंख्या का लगभग 28.15 प्रतिशत तथा 71.84 प्रतिशत है।

----------X----------

प्रस्तावना

योजना के 60 वर्ष बाद भी निर्धनता की समस्या बनी हुई है। यह देश की सबसे प्रमुख समस्या है। यह केवल गरीब व्यक्तियों की ही नहीं वरन् सम्पूर्ण देश की एक महत्वपूर्ण समस्या है। स्वतन्त्रता से पहले कहा जाता था कि 'भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन हैं। यह वाक्य अद्यतन सत्य है। यद्यपि हमारे महानगरों में गगनचुम्बी भवन, चमकते दमकते बाजार, आधुनिक यातायात के साधन, चौड़ी सड़कें, धुंआ उगलता उद्योग, आर्थिक विकास के प्रतीक हैं, लेकिन दूसरी ओर गरीबी की व्यापक समस्या भी विद्यमान है। जिसमें गरीब लोग दोनों समय भरपेट भोजन, तन ढकने के लिये कपड़ा, सिर ढकने के लिए छत की व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं। किसी तरह फुटपाथ तथा झोपड़ी में ही अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। अल्पविकसित देशों में गरीबी की समस्या एक विकराल रूप धारण किये हुये है जिसे व्यापक गरीबी कहा जाता है। कुल मिलाकर निर्धनता से आशय गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली जनसंख्या से है।

महादेव गोविन्द रानाडे भारत की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि "समाज में गरीबी और अमीरी के बीच बढ़ती खाई भारतीय समाज के भविष्य की अनिश्चितता को और अधिक बढ़ाती चली जायेगी।" रानाडे ने भारतीय निर्धनता के 6 कारण बताये हैं-

www.ignited.in

1. भारत की अधिकांश जनता धन के उत्पादन के एकमात्र साधन के रूप में कृषि व्यवसाय पर निर्भर रहती है और कृषि मानसून पर।

2. यहाँ नवीन उद्योगों के विकास की बड़ी बाधा पर्याप्त पूँजी का अभाव है।

3. भारतीय निवेशकर्ताओं में साहस व जोखिम उठाने का अभाव है।

4. सभी क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक दबाब है।

5. निवेश के लिए वित्त भारतीय साहसी परम्परागत ऋण व्यवस्था से ही जुटाते हैं।

6. परम्परागत सामाजिक ढाँचे व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के बीच असंतुलन है।

लेकिन आज भी यदि गहराई से कारणों पर ध्यान दिया जाये तो इस समस्या के मूल में रानाडे द्वारा कही गई बातें ही दिखाई देती हैं। भारत के सन्दर्भ में कृषि व्यवसाय पर अधिक निर्भरता ग्रामीण निर्धनता को बढ़ावा देती है। भारत की दो तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अतः जब तक ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता को दूर कर इन क्षेत्रों का विकास नहीं किया जाता, तब तक भारत वास्तव में आर्थिक शक्ति नहीं बन पायेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है। यह स्वयं में ही मौसमी व्यवस्था है। अतः कृषि व इस पर आधारित उद्योग प्राकृतिक कारणों से मौसमी बेरोजगारी का सामना करते हैं। उत्तरी भारत में किसान औसतन 150 दिन बेकार रहता है। इस बेरोजगारी को बढ़ाने में ग्रामीण शिल्प उद्योग व लघु उद्योगों के पतन की मुख्य भूमिका रही है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन पूर्ण करने हेतु जनपद की दो तहसीलों को चुना गया जिसमें से प्रत्येक तहसील से एक-एक विकास खण्ड तथा प्रत्येक विकास खण्ड से चार ग्रामीण तथा चार शहरी क्षेत्रों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से बीस-बीस परिवारों को दोनों विकास खण्ड से चयनित किया। सम्पूर्ण अध्ययन प्रक्रिया में चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। कुल मिलाकर 160 ग्रामीण तथा 160 शहरी परिवारों से समंकों को एकत्र कर अध्ययन पूर्ण करने की कोशिश की गई।

नव सृजित जनपद प्राचीन समय से दस्यु प्रभावित रहा है जिसका प्रभाव यहाँ के विकास पर पड़ा है। यहां पर निर्धनता को लेकर अभी तक कोई भी शोध नहीं किया गया है। इस कारण शोध निर्धनता पर किया गया है। यहां का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र अति पिछड़ा है। रोजगार के साधन नगण्य हैं। केवल कुछ प्रतिशत जनसंख्या खेती पर आधारित रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। कृषि में भी पैदावार की स्थिति अधिक ठीक नहीं है। जनपद की मृदा कटाव युक्त, कंकरीली है। नदियों की अधिकता के कारण बीहड़ क्षेत्र अधिक है। जिसके कारण ऊबड़ खाबड़ कटाव, खाइयाँ आदि अधिक हैं। कुछ जगह समतल है वहां पर पैदावार बहुत अच्छी होती है। किसान एक वर्ष में चार-चार फसलें पैदा कर रहे हैं जिसमें नगदी फसलें भी शामिल हैं। सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिसका एक प्रभावित कारण दस्यु प्रभावित क्षेत्र का होना है। अध्ययन के समय समंकों को एकत्र करने में भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने निर्धनता मापने के अनेक आधार माने जिसमें से प्राप्त खाद्य कैलोरी में, प्राप्त सुविधा, परिवार की जनसंख्या, पारिवारिक आय तथा कृषि जोत आदि शामिल हैं।

सूचना के स्रोत तथा समंकों का संग्रहण

प्रस्तुत शोध में 160 ग्रामीण व 160 शहरी परिवार को दैवनिदर्शन विधि से चयनित कर अध्ययन का आधार माना गया। जिसमें दो प्रकार से समंकों को एकत्र किया गया-

(i) प्राथमिक समंकों का संग्रहण-

प्राथमिक समंकों को अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुसूची बनाकर साक्षात्कार द्वारा एकत्र किया गया। जिसमें चयनित परिवार से जानकारी प्राप्त की गयी। जिसमें-मुखिया का नाम, स्त्री, पुरुष तथा बच्चों संख्या, आय-व्यय के साधन, व्यक्तिगत तथा सामूहिक आय, उपभोग स्तर, साक्षरता, ऋण ग्रसतता तथा विभिन्न कुरीतियों के बारे में पूछताछ कर जानकारी ली गयी और तालिकाबद्ध कर शोध में प्रयोग किया गया।

(ii) द्वितीयक समंकों का संग्रहण-

प्रस्तावित शोध से सम्बन्धित प्रकाशित शोध-ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों सरकारी तथा अर्द्धसरकारी कार्यालयों द्वारा प्रकाशित तालिकाओं, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय अखबारों, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित संगोष्ठियों तथा

www.ignited.in

सेमिनार से प्राप्त अध्ययन सामग्री का प्रयोग द्वितीयक समंकों को संग्रहित कर शोध पूर्ण करने में सहायता ली गयी।

साक्षात्कार के समय जो आँकड़े प्रस्तुत हुए उनका लगभग मिलान व स्पष्टीकरण सम्बन्धित सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार करने के पश्चात् ही शोध में प्रस्तुत किया गया।

चयनित क्षेत्र के अध्ययन के लिये चयनित परिवार से प्राप्त जानकारी को तालिकाबद्ध किया गया है। इसी आधार पर कृषि जोत का आकार, परिवार की कुल जनसंख्या तथा उम्र के हिसाब से सदस्यों की जानकारी, रोजगार की स्थिति, शिक्षित रोजगार व अशिक्षित रोजगार की स्थिति, पौष्टिकता स्तर, आय-व्यय का ब्यौरा, ऋण की स्थिति तथा बचत आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

सर्वेक्षण एवं विश्लेषण

शहरी व ग्रामीण जनसंख्या में औसत आश्रित तथा कार्यशील जनसंख्या में तालिका नम्बर-अ-(प) में शहरी जनसंख्या में यह प्रकट होता है कि अजीतमल में कुल 20 परिवारों की 92 जनसंख्या में 28 लोग आश्रित हैं तथा 64 लोग किसी न किसी व्यवसाय में कार्यरत हैं। इस प्रकार लगभग 30.43 प्रतिशत लोग आश्रित तथा लगभग 69.56 प्रतिशत लोग कार्यशील हैं।

बाबरपुर में कुल 20 परिवारों की 100 जनसंख्या में 36 लोग आश्रित तथा 64 लोग कार्यशील हैं जो क्रमशः 36 प्रतिशत तथा 64 प्रतिशत हैं।

अटसू में 20 परिवारों में औसत 102 जनसंख्या में 40.20 प्रतिशत आश्रित तथा 59.80 प्रतिशत कार्यशील हैं।

अनन्तराम में 20 परिवारों की 109 जनसंख्या में 46 लोग आश्रित तथा 63 लोग कार्यशील हैं जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 42.20 प्रतिशत तथा 57.80 प्रतिशत है।

सभी शहरी क्षेत्रों में औसतन 37.75 लोग आश्रित तथा 63 लोग कार्यशील हैं। आश्रित तथा कार्यशील लोगों के इस अनुपात से यह प्रतीत हो रहा है कि शहरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

तालिका नम्बर-अ-(ii) ग्रामीण जनसंख्या में औसत आश्रित तथा कार्यशील जनसंख्या का अवलोकन करने से यह प्रकट हुआ कि सांफर गांव में कुल 103 जनसंख्या में 29 लोग औसतन आश्रित तथा 74 लोग औसतन कार्यशील हैं जो कुल जनसंख्या का लगभग 28.15 प्रतिशत तथा 71.84 प्रतिशत है।

अ- शहरी व ग्रामीण जनसंख्या में औसत आश्रित व कार्यशील जनसंख्या

तालिका नं.- अ- (i) शहरी जनसंख्या में औसत आश्रित व कार्यशील जनसंख्या

जनसंख्या का स्वरूप / शहर का नाम	आश्रित		कार्यशील		कुल जनसंख्या (20 परिवारों की)
	कुल संख्या	प्रतिशत	कुल संख्या	प्रतिशत	
अजीतमल	28	30.43	64	69.56	92
बाबरपुर	36	36.00	64	64.00	100
अटसू	41	40.20	61	59.80	102
अनन्तराम	46	42.20	63	57.80	109
औसत	37.75	37.20	63	62.79	100.75

तालिका नं.- अ- (ii) ग्रामीण जनसंख्या में औसत आश्रित व कार्यशील जनसंख्या

जनसंख्या का स्वरूप / गांव का नाम	आश्रित		कार्यशील		कुल जनसंख्या (20 परिवारों की)
	कुल संख्या	प्रतिशत	कुल संख्या	प्रतिशत	
सांफर	29	28.15	74	71.84	103
फूलपुर	24	24.00	76	76.00	100
भीहारी	25	24.51	77	75.49	102
जगन्नाथपुर	21	21.43	77	78.57	98
औसत	24.75	24.52	76	75.47	100.75

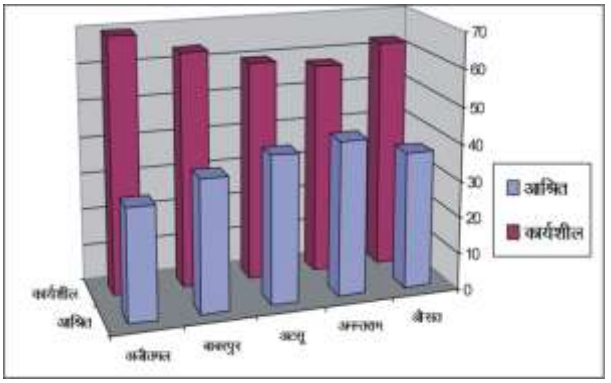

तलिका सं. अ-5 (ख) ग्रामीण जनसंख्या में औसत आश्रित व कार्यशील जनसंख्या

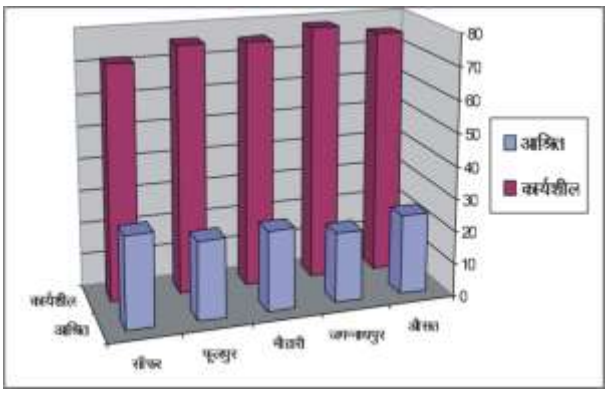

www.ignited.in

फूलपुर गांव में कुल 20 परिवारों की 100 जनसंख्या में 24 लोग आश्रित तथा 76 लोग कार्यशील हैं जो कुल का क्रमशः 24 प्रतिशत तथा 76 प्रतिशत है।

मोहारी गांव में 20 परिवारों की कुल 102 जनसंख्या में 25 लोग आश्रित तथा 77 लोग कार्यशील हैं जो कुल जनसंख्या का 24.51 तथा 75.49 प्रतिशत है।

जगन्नाथपुर गांव में कुल 98 जनसंख्या में 21 लोग आश्रित तथा 77 लोग कार्यशील हैं जो अपनी कुल जनसंख्या का 21.43 प्रतिशत तथा 78.57 प्रतिशत है।

सभी चारों गांवों का औसत लेने पर प्राप्त हुआ कि लगभग 25 लोग आश्रित तथा 75 लोग कार्यशील हैं। केवल कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग ही आश्रित है। इसका अर्थ निकलकर आया कि गांव में लोग किसी न किसी ग्रामीण स्तर के व्यवसाय से जुड़कर अपनी जीविका कमा रहा है। भुखमरी जैसी स्थिति नहीं है। कृषि तथा पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अधिक से अधिक जनसंख्या अपनी जीविका कमा सकती है। इसे गांव का आधार व्यवसाय भी कहा जा सकता है।

निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि युवा वर्ग में महिलाओं की साक्षरता के प्रति जागरूकता आयी है। कुछ आयु वर्ग में दोनों विकास खण्ड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का साक्षरता औसत घटा है जिसका कारण बीच में बालिकाओं का पढ़ाई का छोड़ देना है जिसका कारण गरीबी हो सकता है। अभी महिला शिक्षा के प्रति और सचेत होने की आवश्यकता है, इसके लिये महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा।

महिला पुरुष रोजगार भागीदारी के सम्बन्ध में दोनों विकास खण्डों में आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि प्रत्येक आयु वर्ग में औसतन शहरों तथा गांवों में पुरुषों की रोजगार भागीदारी महिलाओं से अधिक है, विशेषकर 18-50 आयु वर्ग में। शायद इस आयु वर्ग में लोग कार्य योग्य हैं व अपनी जिम्मेदारी परिवार के प्रति समझते हैं। इसलिए महिला तथा पुरुष की रोजगार भागीदारी लगभग बराबर की है। अजीतमल विकास खण्ड में 0-10 आयु वर्ग में गांव तथा शहर दोनों में भागीदारी बराबर की है। इसका कारण है कि अजीतमल शहर भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए शायद बच्चे कृषि, पशुपालन तथा दुकानदारी में अपनी छोटी सी भूमिका प्रस्तुत करते हैं, ऐसा गरीबी के कारण हो सकता है।

बिधूना के शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं तथा स्त्रियों की रोजगार सहभागिता पुरुषों से कम है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर की है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में माना जा सकता है कि अधिकांशतः बालक तथा बालिकायें कृषि एवं पशुपालन रोजगार से जुड़े हैं जबकि शहरों में केवल पुरुष ही रोजगार में संलग्न हैं। दोनों विकास खण्डों में वृद्धावस्था में रोजगार सहभागिता स्त्री तथा पुरुष दोनों में कम है, जिसका कारण वृद्धावस्था के कारण कार्यक्षमता का कम होना है। अजीतमल विकास खण्ड में स्त्री तथा पुरुष दोनों की रोजगार सहभागिता बिधूना विकास खण्ड से अधिक है, इसका कारण अजीतमल विकास खण्ड का अधिक विकसित होना, शिक्षा के अच्छे साधन होना तथा आवागमन की अच्छी व्यवस्था होना है।

दोनों विकास खण्ड अजीतमल तथा बिधूना के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्पष्ट हुआ है कि यहाँ दोनों क्षेत्रों में रोजगार के साधन लगभग समान हैं। इनमें इस जनपद के लोग लिप्त रहकर जीविका अर्जन करते हैं। दोनों विकास खण्डों में कृषि, पशुपालन, सिलाई, राजगीरी, कुटीर उद्योग, दुकानदारी, सरकारी सेवा तथा अन्य रोजगार के साधन हैं, जिससे पारिवारिक आय प्राप्त होती है।

अजीतमल विकास खण्ड में सर्वाधिक पारिवारिक शुद्ध आय औसत शहरी क्षेत्रों में दुकानदारी से है, इसके बाद कृषि तथा पशुपालन से, सरकारी सेवा से भी उचित आय प्राप्त होती है। अन्य व्यवसायों- जैसे सिलाई, राजगीरी, कुटीर उद्योग, रेशमपालन तथा अन्य से कम प्राप्त होती है। इसका कारण अजीतमल के शहरी क्षेत्र मुख्य सड़क के किनारे बसे हैं, जहाँ पर बाजार लगता है, इसलिये दुकानदारी से अधिक आय प्राप्त होती है। चूँकि सारे शहरी क्षेत्र पूर्व में ग्रामीण थे जो अल्प विकसित हैं, अतः लोग अपना मुख्य व्यवसाय खेती करना तथा पशुपालन नहीं छोड़ पाये हैं इसलिये इन स्रोतों से भी आय ठीक प्राप्त हो जाती है। सरकारी सेवा से आय ठीक होने का कारण है इस क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की अधिकता तथा शिक्षा का स्तर उच्च होने के कारण लोग नौकरी तथा सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। अन्य व्यवसाय केवल वही लोग अपना रहे हैं, जिनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है और यदि है तो वह परिवार के खर्चे चलाने के लिये पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस विकास खण्ड के शहरों में सर्वाधिक औसत पारिवारिक शुद्ध तथा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय विभिन्न स्रोतों से अजीतमल, बाबरपुर, अटसू तथा अनन्तराम की घटते हुये क्रम में है।

सन्दर्भ सूची

1. वर्किंग ग्रुप मिनिस्टरी ऑफ एग्रीकल्चर (1994): "एवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टॉक फार कन्जमसन"

www.ignited.in

2. अभिताभ तिवारी (1996-97): "भारत में शिक्षा, विशेष रूप में महिलाओं के सम्बन्ध में", "वार्ता" (XVII) अप्रैल-अक्टूबर, पृ.सं. 115-123.

3. रंजन राय (2000): "पॉवर्टी हाउसहोल्ड, साइज एण्ड चाइल्ड वैलफेयर इन इण्डिया", इकोनोमिक एण्ड पोलीटिकल वीकली, सितम्बर 23, पृ.सं. 3511

4. जी.सी. त्रिपाठी एवं राकेश कुमार पाण्डेय (2001): "इम्पैक्ट ऑफ डवलपमेन्ट ऑन वेजेस एण्ड इम्पलाइमेन्ट ऑफ रूरल लेवर इन इण्डिया", वार्ता (XII) अप्रैल से अक्टूबर, पृ.सं. 13-25.

5. गवर्नमेन्ट ऑफ उ.प्र. (2002): "दसवीं पंचवर्षीय योजना", वॉल्यूम I तथा II

6. वर्ड बैंक (2002): "इण्डिया-पॉवर्टी इन इण्डिया" दि चेलेंज ऑफ उ.प्र.

7. सुभ्राभ्रता भट्टाचार्या (2003): "रूरल मार्केटिंग-दि हाल एक्सपीरियेन्स", हिन्दू सर्वे ऑफ इण्डियन, इन्डस्ट्री

8. एस.पी. तिवारी (2005): "एलीवेशन ऑफ पॉवर्टी इन उ.प्र. एनुअल कॉन्फ्रेन्स", यू.पी. इको. एसो., 18-19 दिसम्बर

9. हिमांशू शेखर सिंह एवं पंचाली सिंह (2005): "रूरल इण्डिया अपॉरच्युनिटी एण्ड चैलेन्ज" एनुअल कॉन्फ्रेन्स, यू.पी. इकोनॉमिक एसोसियेशन, 18-19 दिसम्बर, पृ.सं. 28-37

10. अशोक कुमार (2006): "ग्रामीण भारत में लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति", कुरुक्षेत्र, नवम्बर, पृ.सं. 5.

11. उमेश चन्द्र अग्रवाल (2006): "बाल श्रमिक की विभीषिका", कुरुक्षेत्र, नवम्बर, पृ.सं. 32.

12. नरैनी सिंह जोशी (2006): "ग्रामीण बाजार", योजना, अप्रैल, पृ.सं. 25-29

13. ब्रजेश कुमार तिवारी (2006): "बाल श्रमिक अस्तित्व की खोज में", कुरुक्षेत्र, नवम्बर, पृ.सं. 40.

14. योगेन्द्र के. अलख (2006) : "भारतीय कृषि समस्यायें और सम्भावनायें", योजना, अगस्त, पृ.सं. 17-24.

15. राकेश शर्मा (2006): "बाल श्रम उन्मूलन के लिये आवश्यकता है- वैकल्पिक रोजगारी की", कुरुक्षेत्र, नवम्बर, पृ.सं. 42

15. वाई.एस.पी. थोराट (2006) : "सहकारी ऋण संस्थाओं का पुनर्जीवन", योजना, अगस्त, पृ.सं. 43-46

17. सुभाष सेतिया (2006): "रोजगार के क्षेत्र में महिलायें", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 43.

18. शान्ता सिन्हा (2006): "गरीबों के लिये शिक्षा का हक", योजना, नवम्बर, पृ.सं. 15-19

19. देवी सेट्टी (2006): "सहकारी कृषक स्वास्थ्य कार्यक्रम यशस्विनी", योजना, अप्रैल पृ.सं. 38

20. शंकर दयाल शर्मा (2007): "बीस सूत्रीय कार्यक्रम और ग्रामीण विकास", योजना, जनवरी, पृ.सं. 42

21. इन्दिरा राजारमण (2007): "ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिलायें", योजना, मई, पृ.सं. 28.

22. एस नारायण (2007): "रोजगार सम्भावना पर एक नजर", योजना, अप्रैल, पृ.सं. 25.

23. मथुरा स्वामी (2007): "खाद्य एवं पोषण असुरक्षा को कम महत्व", योजना, मई, पृ.सं. 13.

24. उमेश चन्द्र अग्रवाल (2008): "कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 35.

25. अपराजिता पाण्डया (2008): "जड़ी बूटी का रास्ता"

26. अखिल कुमार मिश्र (2008): "कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनायें", कुरुक्षेत्र, फरवरी, पृ.सं. 24-28.

27. किरन बेदी (2008): "महिला सशक्तिकरण-कुछ विचार", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 15.

28. कुमारी रूपम (2008): "बाल विकास एवं पोषण", योजना, नवम्बर, पृ.सं. 23.

29. जवाहर लाल गुप्ता (2008): "ग्रामीण गरीबी एवं रोजगार के बदलते स्वरूप", कुरुक्षेत्र, फरवरी, पृ.सं. 8.

www.ignited.in

30. निर्मल कुमार आनन्द (2008): "कुपोषण निवारण का सहकारी प्रयास", कुरुक्षेत्र, अक्टूबर, पृ.सं. 45.

31. मंजुला गर्ग एवं पुनीत कुमार (2008): "महिला अस्मिता की चुनौती", योजना, मार्च, पृ.सं. 65.

32. रत्ना कपूर (2008): "वैश्यावृत्ति की रोकथाम और महिला मानवाधिकार", योजना, फरवरी, पृ.सं. 13-14.

33. रत्ना श्रीवास्तव (2008): "बालिका शिक्षा की स्थिति", योजना, सितम्बर, पृ.सं. 31.

34. रहीस सिंह (2008): "गरीबी निर्धारण का अर्थशास्त्र", योजना, नवम्बर, पृ.सं. 47.

35. कुमारी रूपम (2008): "बाल विकास एवं पोषण" योजना, नवम्बर, पृ.सं. 23-24

36. सोना दीक्षित व अरुण कुमार दीक्षित (2008): "हिंसक होता बचपन", योजना, नवम्बर, पृ.सं. 25-26

37. सुधीश कुमार पटेल (2008): "कृषि में रोजगार के बढ़ते अवसर", कुरुक्षेत्र, फरवरी, पृ.सं. 4-6

38. संगीता कुमार (2008): "अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 19

39. रोहनी वी.एस. तथा जयराम भट्ट (2009): "रूरल डवलपमेन्ट एफर्ट इन इण्डिया", इकोनोमिक एफेयर वाल्यूम 45, 4 दिसम्बर, पृ.सं. 199-202

40. अंगद सिंह (2010): "गरीबी निवारण-समस्या और समाधान के रास्ते" नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट पावर्टी डिबेट, भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, नवम्बर, पृ.सं. 12-13.

41. डा. डी. देवनाथन (2010): "पॉवर्टी एलीवेशन प्रोग्राम एण्ड दलित इम्पावरमेन्ट इन तमिलनाडु", नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट पॉवर्टी डिबेट इन इण्डिया, भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, इलाहाबाद, नवम्बर पृ.सं. 16-17.

42. डा. विनीता सिंह (2010): "प्रोब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन ग्लोबलाइजेशन्ड विलेज", नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट पॉवर्टी डिबेट इन इण्डिया, भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, इलाहाबाद, नवम्बर, पृ.सं. 40-41.

43. डा. सलायमा जोव एण्ड टोमी वर्गीज (2010) : "रोल ऑफ वूमेन इम्पावरमेन्ट इन पॉवर्टी एरेडीकेशन एण्ड सोशियो इकोनोमिक चेन्ज इन केरल", नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट पॉवर्टी डिबेट, भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, इलाहाबाद, नवम्बर, पृ.सं. 15-16

44. पद्मा त्रिपाठी (2010): "भारत में निर्धनता की स्थिति का आकलन", नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट पॉवर्टी डिबेट", भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, इलाहाबाद, नवम्बर, 20, 21, पृ.सं. 8-9.

45. पहलाद कुमार (2010): "भारत में गरीबी उन्मूलन में मनरेगा की प्रासंगिकता", नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट पॉवर्टी डिबेट इन इण्डिया, भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, इलाहाबाद, नवम्बर, पृ.सं. 36-37.

46. नवीन पंथ (2010): "गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा", योजना, पृ.सं. 15.

47. अमर उजाला (2011): "भारत में गरीबी" दिनांक 09.07.2011

48. अरविन्द केजरीवाल (2011): "भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था का अधिकार", योजना, अप्रैल, पृ.सं. 13.

49. अजीत कुमार सिंह (2011): "उ.प्र. के ग्रामीण निर्धन में भूमि वितरण का प्रभाव", योजना, नवम्बर, पृ.सं. 28-30.

50. अरुण कुमार वर्मा (2011): "मीडिया एवं सामाजिक परिवर्तन", योजना, अगस्त, पृ.सं. 34.

51. आनन्द कुमार खरे (2011): "बाल श्रम की समस्या एवं निवारण", नेशनल सेमीनार, 29-30 जनवरी, तिलक महाविद्यालय, औरैया

52. एन.सी. सक्सेना (2011): "कृषि भूमि में महिलाओं का उत्तराधिकारी हक", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 11.

53. गौरव कुमार (2011): "बढ़ती आबादी के लिये खाद्यान्न उपलब्धता", योजना, जुलाई

www.ignited.in

54. जयराम रमेश (2011): "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नसंस्थापन विधेयक", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 7.

55. दिव्या पाण्डेय (2011): "मानवाधिकार एवं कन्या भ्रूण हत्या", योजना, अप्रैल, पृ.सं. 43

56. पद्मा त्रिपाठी (2011): "महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता", नेशनल सेमीनार, तिलक महाविद्यालय, औरैया

57. पद्मा त्रिपाठी (2011): "भारत में निर्धनता की वास्तविकता एवं निवारण", अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी, 4, 5, 6 मार्च, वार्ष्णेय कालेज, अलीगढ़, पृ.सं. 9-10.

58. मुकेश शर्मा एवं सुषमा अग्रवाल (2011): "निर्धनता उन्मूलन में रोजगारपरक शिक्षा का महत्व", अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी, 4, 5, 6 मार्च, वार्ष्णेय कालेज, अलीगढ़, पृ.सं. 8-9.

59. टाइम्स ऑफ इण्डिया रिपोर्ट (2011): "पॉवर्टी सिचुयेशन इन इण्डिया", 1 अप्रैल 2011

60. डी.पी. सिंह (2011): "माइग्रेशन पॉवर्टी एण्ड डवलपमेन्ट इन उ.प्र."

61. रेनू गुप्ता (2011) : "नई सदी में भारत-बाल श्रम एक चुनौती", नेशनल सेमीनार, 29-30 जनवरी, तिलक महाविद्यालय, औरैया, पृ.सं. 11-12

62. लीला विसारिया (2011): "भारत की 15वीं जनगणना", योजना, जुलाई, पृ.सं. 6-9

63. वेद प्रकाश अरोरा (2011): "जनगणना का दशकीय सफर", योजना, जुलाई

64. सरस्वती राजू (2011): "बाल लिंग अनुपात-उभरते प्रतिमान", योजना, जुलाई, पृ.सं. 13-19

65. सुभाष शर्मा (2011): "सेवा क्षेत्र में बाल मजदूरी", योजना, सितम्बर, पृ.सं. 17

66. साहब सिंह (2011): "भारत में गरीबी निवारण और आर्थिक विकास- चुनौतियां एवं समस्या समाधान", अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी, 4, 5, 6 मार्च, वार्ष्णेय कालेज, अलीगढ़, पृ.सं. 7

67. शभ्य आलम एवं निर्भय सिंह (2011): "बाल श्रम एक अनसुलझी समस्या", नेशनल सेमीनार, 29-30 जनवरी, तिलक महाविद्यालय, औरैया, पृ.सं. 108-109

68. अजय कुमार सिंह (2012): "ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 23.

69. अशिमा गोयल (2012): "पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन और भविष्य", योजना, जनवरी, पृ.सं. 45.

70. ममता मोहन (2012): "सशक्तिकरण-एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण", योजना, जून, पृ.सं. 43.

71. बजट (2011-12): भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

72. टी.आर. जैन, मुकेश त्रिहान तथा राजू त्रिहान (2012): "भारतीय आर्थिक समस्यायें", पृ.सं. 89-99

73. एफ.ए.ओ. कारपोरेट डाक्यूमेन्ट (रीजनल आफिस फॉर एशिया एण्ड पेसीफिक) "इण्डियन एक्पीरियेंस आन हाउसहोल्ड फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी"

Corresponding Author

Dr. Padma Tripathi*

Associate Professor, Economics, K.K.P.G. College, Etawah